राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14442/2019

महंत रामप्रकाश दास स्वामी उम्र लगभग 48 वर्ष, चेला स्वर्गीय महंत श्री हनुमान दास स्वामी, निवासी दादूद्वार, 1367, निवाई महंत का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. **सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर (राजस्थान)।**
2. **गोविंद दास स्वामी पुत्र श्री दीनदयाल, निवासी ग्राम कंसेल, तहसील फागी, जिला जयपुर (राजस्थान)।**

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : **श्री प्रहलाद शर्मा**, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री एम.एम. रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता

सहायक श्री अमन पारीख, अधिवक्ता

श्री शैलेश शर्मा, एजीसी देवस्थान विभाग के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

आदेश सुरक्षित करने की तारीख : 10 मार्च, 2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

आदेश की तारीख : 2 मई, 2022

न्यायालय द्वारा:

1. याचिकाकर्ता द्वारा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 07.06.2019 के आदेश और आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा पारित दिनांक 15.07.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि राजस्थान

पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 की धारा 23 (इसके बाद '1959 के अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत उनके द्वारा दायर आवेदन संख्या 59/17 को प्रोफार्मा-8 के साथ स्वीकार किया जाए और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर आवेदन संख्या 58/17 को खारिज किया जाए।

2. रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण संख्या 321/71 है और उक्त ट्रस्ट स्वर्गीय महंत श्री रामप्रसाद दास स्वामी द्वारा पंजीकृत किया गया था। महंत श्री रामप्रसाद दास स्वामी की मृत्यु पर, महंत हनुमान दास स्वामी ट्रस्ट के एकमात्र ट्रस्टी बने और महंत हनुमान दास स्वामी का 14.09.2017 को निधन हो गया।

3. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी ने अपने जीवनकाल में दादू संप्रदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार उन्हें 'चेला' के रूप में अपनाया था। याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए सभी दस्तावेजों जैसे चुनाव पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी को उनके पिता के रूप में दिखाया गया है।

4. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को हनुमानजी के मंदिर के पुजारी/प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था और स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के जीवनकाल के दौरान, उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार के संबंध में 25.01.2017 को एक घोषणा की थी।

5. याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की उक्त घोषणा ने याचिकाकर्ता को दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर का महंत घोषित किया था। याचिकाकर्ता ने 14.09.2017 को दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु पर दावा किया है कि उन्होंने 'चेला' के सभी रीति-रिवाजों को पूरा किया था और 'चद्दर दस्तूर' भी दादू संप्रदाय के महंत और संत के पास था।

तदनुसार 19.09.2017 को एक समाचार प्रकाशित किया गया था और याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रधान पीठ, दादू संप्रदाय (संप्रदाय), नारायण द्वारा

प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था।

6. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि 05.10.2017 को उन्होंने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के समक्ष प्रोफार्मा-8 के साथ 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के स्थान पर ट्रस्ट रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया, क्योंकि याचिकाकर्ता को दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर का महंत घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त आवेदन आवेदन संख्या 59/17 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

7. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज की और साथ ही, प्रोफार्मा-8 के साथ 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर के महंत के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके लिए महंत संतोष दास के परिवार के सदस्यों द्वारा 'चद्दर दस्तूर' किया गया था और इसके चलते ट्रस्ट के संशोधित संविधान के अनुसार, दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी के स्थान पर ट्रस्ट रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर उक्त आवेदन आवेदन संख्या 58/17 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी ने अपने जीवनकाल के दौरान ट्रस्ट के संविधान में संशोधन के लिए एक आवेदन संख्या 51/16 भी दायर किया था और ट्रस्ट के संशोधित संविधान को भी प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में संशोधित संविधान के साथ संशोधित संविधान प्रस्तुत करने के लिए 06.02.2017 को फिर से एक आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दायर उक्त आवेदन पर, दलीलों की सुनवाई 29.05.2017 को हुई थी, हालांकि, 14.09.2017 को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु पर, संविधान के संशोधन के लिए शुरू की गई कार्यवाही में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और इस प्रकार, 11.03.2019 को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग,

जयपुर द्वारा केस नंबर 51/2016 की कार्यवाही को हटा दिया गया।

9. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि बिना कोई आवेदन दायर किए सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर ने 11.03.2019 को ही कार्यवाही रद्द कर दी, लेकिन दिनांक 07.06.2019 के आदेश को पारित करते हुए, केस नंबर 51/2016 में एक अलग आदेश पत्र तैयार किया गया था, जिसके तहत संशोधित संविधान को स्वीकार किया गया है और उक्त संशोधित संविधान के आधार पर, इसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है।

10. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर ने दिनांक 07.06.2019 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन संख्या 59/2017 को 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत खारिज कर दिया और 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन संख्या 58/2017 को स्वीकार कर लिया और यह आदेश दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम रजिस्टर नंबर 4 में दर्ज किया जा सकता है।

11. 15.07.2019.दिनांक 07.06.2019 के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए याचिकाकर्ता ने आयुक्त, देवस्थान विभाग के समक्ष अपील की और उक्त अपील को 15.07.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग और आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा क्रमशः 07.06.2019 और 15.07.2019 को पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:—

> 12क. निचली दोनों अदालतों ने इस मामले के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है कि याचिकाकर्ता को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा 'चेला' के रूप में अपनाया गया था और याचिकाकर्ता को 'चेला' के रूप में लेने के सभी रीति-रिवाजों का पालन किया गया था और याचिकाकर्ता से संबंधित सभी दस्तावेजों में उसे स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के बेटे के रूप में दिखाया गया है। स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 25.01.2017 को निष्पादित

घोषणा को भी नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसमें उन्हें दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर के ट्रस्ट का महंत घोषित किया गया था।

12ख. निचली अदालतें इस बात को ध्यान में रखने में विफल रही हैं कि प्रत्यर्थी नंबर 2 कभी भी दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर में नहीं रहा और दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर में कोई 'चद्दर दस्तूर' नहीं किया गया था, लेकिन 'चद्दर दस्तूर' समारोह कंसेल गांव में आयोजित किया गया था और इस तरह, प्रत्यर्थी नंबर 2 का दादू द्वारा रामगंज बाजार, जयपुर से कोई लेना-देना नहीं था।

12ग. निचली दोनों अदालतों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा प्रस्तुत ट्रस्ट के संशोधित संविधान को उनके जीवनकाल में न तो मंजूरी दी गई थी और न ही स्वीकार किया गया था और इसके विपरीत, केस नंबर 51/2016 में उनके द्वारा दायर आवेदन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उनकी ओर से कोई पेश नहीं हो रहा था। 11.03.2019 को तैयार किए गए आदेश पत्र में, उसी दिन बाद के आदेश में उल्लेख किया गया था कि उसी ट्रस्ट से संबंधित कार्यवाही 25.03.2019 को लंबित थी। याचिकाकर्ता ने सभी मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए 25.03.2019 को कोई आवेदन दायर नहीं किया है और सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ने अपने दम पर सभी मामलों को टैग किया और गलत आदेश पत्र तैयार किए गए।

12घ. 1959 के अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार केवल ट्रस्ट रजिस्टर में बदलाव किया जा सकता है, हालांकि, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ने 1959 के अधिनियम की धारा 23 में प्रदत्त शक्ति से परे कार्रवाई की है और उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एकमात्र ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है जबकि 1959 के अधिनियम की धारा 23 नए ट्रस्टी की नियुक्ति की शक्ति प्रदान नहीं करती है और केवल ट्रस्ट रजिस्टर में बदलाव किए जा सकते हैं।

12ङ. निचली अदालतें इस बात पर विचार करने में विफल रही हैं कि

स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधित संविधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे 07.06.2019 से पहले स्वीकार या अनुमोदित नहीं किया गया था।

12च. निचली दोनों अदालतें 1959 के अधिनियम की धारा 23, 38 और 40 में निहित प्रावधानों पर विचार करने में विफल रही हैं क्योंकि ट्रस्टी की नियुक्ति के संबंध में विवाद को मौजूदा ट्रस्टी की मृत्यु पर सिविल कोर्ट को संदर्भित करना आवश्यक है और चूंकि वर्तमान मामले में एकमात्र ट्रस्टी, अर्थात् स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु 14.09.2017 को हुई थी, इस तरह केवल याचिकाकर्ता को कार्यकारी ट्रस्टी के रूप में माना जाना आवश्यक था, क्योंकि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक घोषणा निष्पादित की थी।

12छ. निचली अदालतों ने सिविल अदालतों में सिविल कार्यवाही में पारित आदेशों पर अपने निष्कर्षों को गलत तरीके से आधारित किया है, जहां सिविल न्यायालयों ने पहले ही देखा था कि पक्षों द्वारा दायर किए गए मुकदमे किसी भी तरह से उत्तराधिकार के उद्देश्य से नहीं थे।

13. दोनों प्रत्यर्थियों ने अपने-अपने उत्तर दाखिल किए हैं।

14. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दादूदयालजी महाराज के शिष्यों के रूप में दादूपंथी समाज का इतिहास और पृष्ठभूमि दी है, जिसे 16$^{वीं}$ शताब्दी से मौजूद बताया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील दी है कि वर्ष 2003 में महंत राम प्रसाद दासजी की मृत्यु के बाद, स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी को महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार द्वारा दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर के महंत के रूप में चुना और नामित किया गया था। दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी अविवाहित और महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार से संबंधित बताए जाते हैं।

15. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील दी है कि डॉ. दयाराम स्वामी महंत राम प्रसाद दासजी महाराज के मुख्य शिष्य (शिष्य) भी थे और वह दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी के गुरु भाई थे और दादू द्वार, रामगंज बाजार, जयपुर में

रहते थे और चूंकि वह एक विवाहित व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें खालसा परिवार द्वारा महंत के रूप में नहीं चुना गया था।

16. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील दी है कि 14.09.2017 को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु पर, उन्हें खालसा परिवार द्वारा महंत के रूप में नामित किया गया था और उसके बाद, 10.10.2017 को नाम बदलने के लिए सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के समक्ष प्रोफार्मा नंबर 8 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने खुद को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी का उत्तराधिकारी बताते हुए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था।

17. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार का सदस्य नहीं है और वह दिग्गी मालपुरा से संबंधित है और वह जयपुर के आमेर में एक हनुमान मंदिर में पुजारी के रूप में काम कर रहा था और स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु के बाद, उसने दादू द्वार रनगंज बाजार, जयपुर की इमारत पर अतिक्रमण किया और जाली दस्तावेज भी तैयार किए।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दलील दी है कि दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु के 12 दिनों के बाद, महंत संतोष दासजी महाराज और दादू पंथी समाज के खालसा परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए और प्रत्यर्थी संख्या 2 को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के उत्तराधिकारी और 'चेला' के रूप में नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तर के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 का 'चादर दस्तूर' और जुलूस (जुलूस) और निमंत्रण पत्र आदि को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मामले के गुण-दोष के आधार पर तर्क दिया है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग ने दोनों आवेदन प्राप्त करने पर साक्ष्य दर्ज किए और प्रत्यर्थी संख्या 2 को उत्तराधिकारी और स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के स्थान पर महंत घोषित किया और उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म नंबर 6 के अनुसार, उत्तराधिकार की प्रक्रिया दादू समाज द्वारा की गई थी।

स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के दिनांक 18.04.2017 के हलफनामे द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है और संशोधित संविधान में इसकी पुष्टि की गई है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया था कि महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार के सदस्य को ही महंत का पद दिया जाएगा और जो नीहंग (अविवाहित) भी होना चाहिए।

20. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार के सदस्य राम सरन स्वामी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा और घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को खुद को वारिस और उत्तराधिकारी घोषित नहीं करने के लिए आदेश पारित किया गया था और ऐसे आदेश की बावजूदयाचिकाकर्ता द्वारा 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के समक्ष आवेदन दायर किया गया था।

21. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के जीवित रहने के समय दो अलग-अलग मुकदमे लंबित थे, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 दो ने पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन दायर किए थे, जबकि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें उत्तराधिकारी माना गया था।

22. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कहा है कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के साथ-साथ आयुक्त, देवस्थान विभाग ने कोई अवैधता नहीं की है और तथ्यों की जांच करने पर, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन और उनके द्वारा दायर अपील को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

23. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी रिट याचिका पर उत्तर दाखिल किया है। ऑर्डरशीट में बदलाव के आरोप को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह भी दलील दी है कि सभी पक्षों को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर दिया गया था और पूरे गुण-दोष पर विचार करने के बाद, आदेश पारित किए गए हैं।

24. सहायक आयुक्त ने आवेदन संख्या 58/17 और 59/17 का निपटारा करते हुए न्याय के हित में सुनवाई के लिए आवेदन संख्या 51/16 को भी लिया था। आवेदन संख्या 51/16 में, पूर्व एकमात्र ट्रस्टी स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी ने 18.04.2017 के अपने बयान और 22.03.2017 के हलफनामे में ट्रस्ट के संशोधित संविधान को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था और आवेदन संख्या 58/17 और 59/17 में पार्टियों ने भी उक्त संशोधित संविधान में सहमति व्यक्त की थी और अपना विश्वास व्यक्त किया था। आवेदन संख्या 51/16 में, स्वरूप को अनुमति दी गई थी और तदनुसार, इसकी अनुमति दी गई थी।

25. प्रत्यर्थी संख्या 2 के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एमएम रंजन ने निम्नलिखित तर्क पेश किए हैं:—

25क. सहायक आयुक्त और देवस्थान विभाग के आयुक्त दोनों ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता महंत संतोष दास के खालसा परिवार का सदस्य नहीं है और इस तरह, संविधान में संशोधन के मद्देनजर उसे स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था।

25ख. स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दायर आवेदन संख्या 51/16 में, उनका बयान 18.04.2017 को दर्ज किया गया था और यह कहीं भी खुलासा नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता को महंत के रूप में नियुक्त किया गया था और संशोधित संविधान के अनुसार, जिसमें उत्तराधिकार का तरीका प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता दोनों आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था, उसे महंत के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था यानी न तो वह महंत संतोष दास के खालसा परिवार का सदस्य था और न ही वह नीहांग (अविवाहित) था।

25ग. याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवेदन संख्या 51/16 में हेरफेर है और अलग आदेश पत्र तैयार किया गया था, अधिवक्ता ने कहा कि लिपिक और सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा स्क्राइब द्वारा लिखे

गए हस्ताक्षर के बाद कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ था और फिर उन्होंने प्रविष्टियों में बदलाव दर्ज करने के लिए 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत फाइल को अन्य आवेदनों के साथ संलग्न किया।

25घ. चूक में बर्खास्तगी के संबंध में कोई निर्णायक आदेश पारित नहीं किया गया था क्योंकि आदेश 20 नियम 3 सीपीसी के अनुसार, आदेश को केवल पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद पारित किया गया माना गया था और लिपिक द्वारा नोटशीट पर कोई हस्ताक्षर नहीं लिखे गए थे।

25ङ. सिविल कोर्ट ने महंत संतोष दासजी के खालसा परिवार के सदस्य राम सरन स्वामी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे और दो अन्य मुकदमों में स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के खिलाफ 18.09.2019 और 22.04.2019 के आदेशों के तहत जांच करने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी का उत्तराधिकारी घोषित करने और भारत के संविधान की धारा 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों पर विचार करने का आदेश पारित किया था, जिन तथ्यों की दोनों न्यायालयों द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा पुनः जांच के लिए नहीं लिया जा सकता है।

26. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

27. मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले, यह न्यायालय पहले वर्तमान मामले में निर्विवाद तथ्यों को स्पष्ट करना चाहेगा, जो इस प्रकार हैं:–

27(क) याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रोफार्मा-8 के साथ 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

27(ख) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रोफार्मा-8 के साथ 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन भी दायर किया।

27(ग) स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी ने अपने जीवनकाल के दौरान

ट्रस्ट के संविधान में संशोधन के लिए आवेदन संख्या 51/2016 दायर किया और संशोधित संविधान भी प्रस्तुत किया।

27(घ) स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी ने सहायक आयुक्त के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया और 18.04.2017 को अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि संशोधित संविधान दाखिल किया जाना था और अपेक्षित प्रविष्टि की जानी थी।

27(ड.) याचिकाकर्ता ने 22.04.2019 को अपनी जिरह के दौरान संशोधित संविधान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और याचिकाकर्ता दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से अवगत था।

27(च) याचिकाकर्ता ने दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दायर दस्तावेजों और संशोधित संविधान को स्वीकार कर लिया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम कार्यकारी ट्रस्टी के रूप में शामिल नहीं था।

27(छ) सिविल वाद संख्या 155/2018 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर जिले की न्यायालय में लंबित था, जिसमें स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी एक पक्ष थे और उनकी मृत्यु पर, मुकदमे में पक्षकार के रूप में पक्षकार बनने के लिए दो अलग-अलग आवेदन दायर किए गए थे और याचिकाकर्ता-महंत रामप्रकाश दास स्वामी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 2-गोविंद दास स्वामी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।

27(ज) सिविल वाद संख्या 352/2012 स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के बीच लंबित था और प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 22.04.2019 के आदेश के तहत उक्त सिविल सूट में पक्षकार बनाया गया था।

27(झ) सिविल वाद संख्या 121/2012 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर मेट्रोपॉलिटन की न्यायालय में लंबित था, जिसमें 10.07.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 1809/2017 में आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को खुद को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी का उत्तराधिकारी घोषित करने से रोक दिया गया था।

28. इस न्यायालय ने पाया कि सहायक आयुक्त ने दिनांक 07.06.2019 का आदेश पारित करते हुए सामान्य आदेश द्वारा तीन आवेदनों पर निर्णय लिया है और याचिकाकर्ता द्वारा 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर आवेदन संख्या 59/2017 को खारिज कर दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन संख्या 58/2017 को स्वीकार कर लिया गया है और स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दायर आवेदन संख्या 51/2016 को ट्रस्ट के संशोधित संविधान को रिकॉर्ड में लेने की अनुमति दी गई है।

29. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा याचिकाकर्ता को 'चेला' के रूप में अपनाए जाने के तथ्य और याचिकाकर्ता को 'चेला' के रूप में लेने के सभी रीति-रिवाजों और याचिकाकर्ता के पक्ष में दस्तावेजों की अनदेखी की है, जिसमें उन्हें दिवंगत महंत हनुमान दास स्वामी के बेटे के रूप में दिखाया गया है, इसे नजरअंदाज किए जाने पर, यह न्यायालय पाती है कि सहायक आयुक्त ने दोनों पक्षों के नेतृत्व में सभी मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखने के बाद, आक्षेपित आदेश पारित किया है।

30. यह न्यायालय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं करती है कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा उनके पक्ष में 25.01.2017 को की गई घोषणा को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के उत्तराधिकारी/कार्यकारी ट्रस्टी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने पाया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के बयान को ध्यान में रखा है जो उन्होंने अपने आवेदन में दिया था और जिससे उन्होंने वर्तमान याचिकाकर्ता के पक्ष में की गई किसी भी घोषणा का खुलासा नहीं किया था। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखा है, जो उनके द्वारा दायर आवेदन में उनकी मृत्यु से पहले दर्ज किया गया था और ट्रस्ट-विलेख में ट्रस्टी के नामांकन के लिए संशोधित संविधान को भी ध्यान में रखा गया था।

31. निचले न्यायालयों को दिए गए सबूतों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्रमांक 10 में संशोधित संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि प्रबंध ट्रस्टी की मृत्यु के बाद, अगला महंत श्री दादू पंथी महंत संतोष दासजी महाराज के खालसा परिवार से होगा और उसे 'नीहंग' भी होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे कुंवारा होना चाहिए।

32. इस न्यायालय ने पाया कि पात्रता पर विचार करते हुए, जैसा कि संशोधित संविधान में प्रदान किया गया है, निचले दोनों न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता कार्यरत ट्रस्टी के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और इस प्रकार, निचले न्यायालयों द्वारा तथ्यों की ऐसी रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

33. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस दलील पर विचार करते हुए कि ट्रस्ट के संशोधित संविधान को स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी के जीवनकाल में न तो मंजूरी दी गई थी और न ही स्वीकार किया गया था और उनके द्वारा केस नंबर 51/2016 में दायर आवेदन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उनकी ओर से कोई भी मौजूद नहीं था और 11.03.2019 को इसी आशय का आदेश पत्र भी तैयार किया गया था, लेकिन फाइल को अन्य लंबित आवेदनों के साथ टैग करने के लिए फिर से आदेश पत्र तैयार किया गया था, अतः स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा दायर आवेदन संख्या 51/2016 पर फैसला करते समय सहायक आयुक्त द्वारा बड़ी अवैधता की गई है, इस न्यायालय ने 11.03.2019 के आदेश पत्र को देखने के बाद पाया कि शुरू में आवेदन संख्या 51/2016 में कार्यवाही को छोड़ने के लिए आदेश पत्र तैयार किया गया था, लेकिन आदेश पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं था और बाद में, आदेश पत्र पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था कि एक ही ट्रस्ट से संबंधित, अन्य मामलों को 25.03.2019 को सूचीबद्ध किया जाना था और इस प्रकार, आवेदन संख्या 51/2016 को भी अन्य मामलों के साथ टैग कर दिया गया था।

34. इस न्यायालय ने दिनांक 07.06.2019 के आदेश पत्र का भी अध्ययन

किया है जिसमें सहायक आयुक्त ने दर्ज किया है कि सभी फाइलों को एक साथ टैग किया गया था और सभी पक्षों ने संशोधित संविधान के मुद्दे पर निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त की थी।

35. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की यह दलील कि 1959 के अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार केवल ट्रस्ट रजिस्टर में बदलाव किए जा सकते हैं और सहायक आयुक्त ने अपनी शक्ति से परे जाकर कार्रवाई की और उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एकमात्र ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया, इस न्यायालय द्वारा यह कहने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन किया था जिसमें उन्होंने स्वयं प्रार्थना की थी। वह दिवंगत गोपाल दासजी महंत के शिष्य/उत्तराधिकारी थे और उनकी प्रार्थना प्रबंध न्यासी के रूप में ट्रस्ट में आवश्यक बदलाव करने की थी। याचिकाकर्ता को एक ही समय में दो नौकाओं पर पैर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक तरफ वह प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने और अनुमति देने के लिए सहायक आयुक्त की शक्तियों पर संदेह करता है और दूसरी तरफ वह खुद 1959 के अधिनियम की धारा 23 के तहत एक आवेदन दायर करके उसी घोषणा की मांग करता है।

36. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि नीचे दिए गए न्यायालय मौजूदा ट्रस्टी की मृत्यु पर ट्रस्टी की नियुक्ति के संबंध में 1959 के अधिनियम की धारा 23, 38 और 40 के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे, इस न्यायालय ने पाया कि सिविल मुकदमा जो पक्षों अर्थात स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी और अन्य व्यक्तियों के समक्ष लंबित था, 1959 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, उत्तराधिकारी या कार्यकारी ट्रस्टी का मुद्दा सहायक आयुक्त के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में था और केवल निषेधाज्ञा और अन्य संपत्ति/सिविल विवाद के संबंध में, सिविल कोर्ट विभिन्न मामलों में उलझा हुआ था।

37. इस न्यायालय को लोक न्यास के पंजीकरण आदि से संबंधित 1959 के अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के दायरे पर भी विचार करना अपेक्षित है। इस

न्यायालय ने पाया कि 1959 के अधिनियम की धारा 17 में सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण का प्रावधान है और 1959 के अधिनियम की धारा 18 में सहायक आयुक्त द्वारा पंजीकरण के लिए जांच करने का प्रावधान है। 1959 के अधिनियम की धारा 19 में 1959 के अधिनियम की धारा 18 के तहत की गई जांच के समापन पर सहायक आयुक्त द्वारा कारणों के साथ निष्कर्ष देने का प्रावधान है। 1959 के अधिनियम की धारा 20 में 1959 के अधिनियम की धारा 19 के तहत दर्ज सहायक आयुक्त के निष्कर्षों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान किया गया है और पीड़ित व्यक्ति आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

38. इस न्यायालय ने पाया कि 1959 के अधिनियम की धारा 21 में सहायक आयुक्त द्वारा किए जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टियों का प्रावधान है। 1959 के अधिनियम की धारा 22 सिविल मुकदमा दायर करने के माध्यम से रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि को चुनौती देने का अधिकार देती है।

39. 1959 के अधिनियम की धारा 23, वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक होने के नाते, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:–

> "23. परिवर्तन- (1) जहां रजिस्टर में दर्ज किसी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन होता है, वहां कार्यरत न्यासी ऐसे परिवर्तन के घटित होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर या, जहां ऐसे लोक न्यास के प्रशासन के हित में ऐसी प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन वांछित है, कार्यरत न्यासी ऐसे परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना विहित प्रपत्र और रीति में सहायक आयुक्त को देंगे।
>
> (2) रजिस्टर में प्रविष्टियों की शुद्धता की पुष्टि करने या यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या रजिस्टर में दर्ज किसी भी विवरण में कोई बदलाव हुआ है, सहायक आयुक्त जांच कर सकता है।
>
> (3) यदि, उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपधारा (2) के अधीन ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझे, सहायक आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उस विशेष लोक न्यास के संबंध में रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों में से किसी में परिवर्तन हुआ है या आवश्यक है, तो वह उसके कारणों के साथ निष्कर्ष दर्ज करेगा और धारा 29 के उपबंध ऐसे निष्कर्षों पर लागू होंगे जैसे कि धारा 19 के तहत एक निष्कर्ष पर लागू होता है।
>
> (4) सहायक आयुक्त उपधारा (3) के तहत दर्ज निष्कर्षों के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों को संशोधित करेगा या, यदि उससे अपील दायर की गई है, तो ऐसी अपील पर आयुक्त के निर्णय के अनुसार और धारा 21

और 22 के प्रावधान ऐसी संशोधित प्रविष्टियों पर लागू होंगे जैसा कि वे मूल प्रविष्टियों पर लागू होते हैं।

40. इस न्यायालय ने पाया कि यदि रजिस्टर में दर्ज किसी भी प्रविष्टि में कोई बदलाव होता है, तो कार्यरत ट्रस्टी इसे निर्धारित फॉर्म में रिपोर्ट कर सकता है और सहायक आयुक्त को परिवर्तन या प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना भी दे सकता है। अधिनियम 1959 की धारा 23 की उपधारा (2) सहायक आयुक्त को रजिस्टर में पहले से दर्ज विवरणों के संबंध में हुए किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए जांच करने की शक्ति देती है। 1959 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच करने के बाद, यदि सहायक आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि लोक न्यास के संबंध में रजिस्टर में दर्ज किसी प्रविष्टि में परिवर्तन हुआ है या आवश्यक है, तो वह उसके कारणों के साथ एक निष्कर्ष दर्ज करेगा।

41. इस न्यायालय ने पाया कि मामले के वर्तमान तथ्यों में, पहला कदम स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी द्वारा संविधान में बदलाव के लिए एक आवेदन देकर उठाया गया था और उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद एक कार्यकारी ट्रस्टी के नामांकन का एक विशिष्ट प्रावधान भी डाला था। इस न्यायालय ने पाया कि स्वर्गीय महंत हनुमान दास स्वामी की मृत्यु हालांकि उनके आवेदन पर किसी भी अंतिम निर्णय से पहले हो गई थी, लेकिन, उनकी मृत्यु से पहले दर्ज किए गए उनके बयान ने स्पष्ट रूप से कार्यकारी ट्रस्टी के नामांकन की विधि का वर्णन किया था।

42. इस न्यायालय ने पाया कि सहायक आयुक्त को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि संविधान के अनुसार नामांकन हुआ था या नहीं। सहायक आयुक्त के पास पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दो अलग-अलग आवेदन भी थे अर्थात याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा और पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विचार करने के बाद और संशोधित संविधान के अनुपालन में, यदि निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, तो इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका में साक्ष्य की फिर से छानबीन करना संभव नहीं होगा।

43. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्ति यह देखने के लिए है कि अधिकारियों ने उचित तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है या नहीं। साक्ष्य या तथ्यों की छानबीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं होगा। **जय सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम एवं अन्य, (2010) 9 एससीसी 385** में प्रकाशित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया गया है कि उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और नीचे दिए गए न्यायालयों या वैधानिक/अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबूतों की फिर से छानबीन नहीं कर सकता है जब तक कि गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। निर्णय के प्रासंगिक पैरा को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

> "15. हमने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है। इससे पहले कि हम इसमें शामिल तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों पर विचार करें, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को देख सकते हैं। निस्संदेह इस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ सांविधिक या अर्ध-न्यायिक अधिकरण, अपने प्राधिकार की सीमा के भीतर निहित शक्तियों का प्रयोग करें। उच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है कि वे कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। उच्च न्यायालय को अधीक्षण और/या न्यायिक संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी, जहां उच्च न्यायालय में कोई संशोधन या अपील नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र, कुछ मायनों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति और अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है। हालांकि, इस प्रसिद्ध कहावत को याद रखना अच्छा है कि शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके प्रयोग में अधिक देखरेख और सावधानी होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इतनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग बड़ी सावधानी, सावधानी और सतर्कता के साथ करे। क्षेत्राधिकार का प्रयोग अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त बाधाओं के भीतर होना चाहिए। इसका इस्तेमाल 'चीन की दुकान में बैल' की तरह नहीं किया जा सकता है, ताकि हर उस न्यायालय, या अधिकरण के फैसले की सभी त्रुटियों को ठीक किया जा सके, जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं

के भीतर कार्य कर रहा है। इस सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा या कानून या न्याय के मौलिक सिद्धांतों के घोर दुरुपयोग में आदेश पारित किए गए हैं।

16. उच्च न्यायालय हल्के तौर पर या उदारतापूर्वक एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और सबूतों की फिर से छान-बीन नहीं कर सकता है। आम तौर पर, यह नीचे दिए गए न्यायालयों या वैधानिक/अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। सबूतों की फिर से सराहना करने की शक्ति केवल दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में उचित होगी जहां गंभीर अन्याय किया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय हस्तक्षेप न करे। इस तरह की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का कोई उल्लंघन न हो।

44. इस न्यायालय को आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं मिली है और याचिकाकर्ता ऐसा कोई आधार नहीं उठा पाया है जो उसे सहायक आयुक्त और आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा पारित आदेशों को रद्द करके राहत प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

45. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका, गुणागुण से रहित होने के कारण, खारिज की जाती है।

(अशोक कुमार गौड़), न्यायमूर्ति

Solanki DS, PS

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।